

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 77/18

GCMS NO 2018/00212

1. रामेश्वर सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
2. छीतर सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
3. रघुवीर सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
4. नारायण सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
5. नयन सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
6. रमेश सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
7. सुरेश सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
8. प्रेम सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
9. विक्रम सिंह पुत्र हरनाथ सिंह
10. राजूसिंह पुत्र हरिसिंह
11. दिलीप सिंह पुत्र हरि सिंह
12. मुन्नी कंवर बेवा हरि सिंह
13. भानू प्रताप पुत्र किशन सिंह
14. राजा सिंह पुत्र किशन सिंह
15. रेखा पत्नि किशन सिंह जातियान राजपूत निवासीयान मोरपा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास
2. नायब तहसीलदार उप तहसील बरनाला
3. पटवार हल्का मोरपा
4. सचिव ग्राम पंचायत मोरपा पंचायत समिति बामनवास
5. समुन्द्र सिंह पुत्र कंचन सिंह जाति राजपूत निवासी मोरपा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

रेसपो

(अपील विरुद्ध मु0नं0 31/10 निर्णय व डिक्री दिनांक 4.7.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री योगेश शर्मा

अभिभाषक रेसपो पैरोकार सरकार, श्री मो0इस्लाम खान

दिनांक 8.1.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 4.7.17 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलाट के पिता हरनाथ सिंह ने एक वाद पत्र बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक ख0न0 181 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा मोरपा मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

स्थित है। जिसकी खातेदारी साबिक रिकार्ड में हरनाथ सिंह के नाम दर्ज है। जिसे वादी ही वहसिकय काबिज काश्त करता चला आ रहा है। साबिक ख०न० 181 का भू प्रबंध विभाग द्वारा ख०न० 453 रकबा 17 ऐयर कायम किया गया है व खातेदारी साबिक रिकार्ड के अनुसार वादी के नाम दर्ज है। वादी द्वारा अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में एक चाह का निर्माण करवाया गया जो वर्तमान में मौजूद है। साबिक रिकार्ड के अनुसार वादी के नाम 26 ऐयर भूमि दर्ज होनी चाहिए थी। लेकिन भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियों ने वादी के नाम केवल ख०न० 452 रकबा 17 ऐयर ही खातेदारी में दर्ज की गई है। जो साबिक रिकार्ड के अनुसार 9 ऐयर रकबा कम है। उक्त कम रकबे के लिए वादी अलग से वाद प्रस्तुत करेगा। वादी उक्त आराजीयात का वैध खातेदार है। प्रतिवादीगण का वादी की इस खातेदारी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। उक्त साबिक ख०न० से बने हाल ख०न० 453 रकबा 17 ऐयर का वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण को वादी की भूमि को किसी अन्य के नाम दर्ज करने या भूमि को सिवायचक या अन्य किसी प्रकार की इन्द्राज दुरुस्ती करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण मात्र रजिस्टर्ड विक्रय पत्र या वैध हस्तांतरण विलेख के आधार पर या किसी सक्षम न्यायालय के आदेश पर ही वादी की भूमि को किसी अन्य के नाम अंतरित कर सकते हैं। अन्यथा वादी की भूमि को सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 ने ग्रामवासियों से साज कर वादी को नुकसान पहुँचाने की नीयत से बिना किसी प्रकार की कोई न्यायिक प्रक्रिया अपनाये बिना वैध खातेदार को सुने मनमाने तरीके से फर्जी तरीके से अवांछित लाभ प्राप्त करने की नियत से वादी की खातेदारी की भूमि ख०न० 453 में से 7 ऐयर भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा नक्शे में तरमीम कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा उप तहसील बरनाला के आदेश की पालना में ख०न० 839/453 रकबा 10 ऐयर व 453 रकबा 7 ऐयर नक्शे में तरमीम कर दिया तथा ख०न० 453 को , जो कि चाह है सिवायचक दर्ज कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा जानबूझकर कूटरचित रचना रचकर वादी की खातेदारी की भूमि व नक्शे में वादी को नुकसान करने की गर्ज से समस्त कार्यवाही की है। जिसके लिए वादी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करेगा। राजस्व रिकार्ड में की गई उक्त फर्जीयत का ज्ञान वादी को नहीं था। पटवारी हल्का से नकल लेने से रकबा कम होने का ज्ञान हुआ। वादी द्वारा उक्त रकबे का कम करने के बाबत प्रतिवादी संख्या 2 व 3 से कहा तो उनके द्वारा कोई संतोषप्रद जबाब नहीं देने पर वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। इस प्रकार वादी की खातेदारी में से कम किये गये रकबे 7 ऐयर को पुनः वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाकर उसी अनुसार नक्शे में दुरुस्त किया जावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी की खातेदारी की उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करे वादी को बेदखल नहीं करे। किसी प्रकार का निर्माण या अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलांट के पिता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय से चाही गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद का निस्तारण राजस्व लोक अदालत बाटौदा में किया गया है जो गलत होने से निरस्त योग्य है। राज्य सरकार के द्वारा लोक अदालत केम्पो में प्रकरणों का निस्तारण करने का आदेश दिया गया था जिनमें दोनों पक्षकारान लोक अदालत केम्पो में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप में राजीनामा पेश करें। उक्त प्रकरण में न तो पक्षकारान उपस्थित रहे हैं न ही पक्षकारान को कोई सूचना दी गई है न ही पक्षकारान द्वारा निर्धारित प्रारूप में राजीनामा पेश किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमानी तरीके से निर्णय पारित किया गया है। जो निरस्त योग्य है। निर्णय के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही मात्र रेस्पों को कानून से उपर उठकर अनुतोष देने का मन बनाकर निर्णय दिया गया है जो गलत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि वादी द्वारा दुरुस्ती चाही गई है जो बिना साक्ष्य लिये तथा दस्तावेजी के प्रदर्शित हुए बिना तय नहीं की जा सकती है। बिना तनकी बिचरीत किये तथा बिना साक्ष्य लिये प्रकरण का निस्तारण कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सुने बिना ही एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। दिनांक 4.7.17 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत केम्पो बाटौदा में पत्रावली की कोई सुनवाई नहीं की गई। अपीलांट व रेस्पों की ओर से कोई उपस्थित नहीं था न तो पत्रावली पर रेस्पों द्वारा दिया गया कोई प्रार्थना पत्र है न ही उपस्थिति के हस्ताक्षर है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध निर्णय पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। प्रकरण में अपीलार्थी को अधिवक्ता द्वारा लगातार तारीख पेशियां दी गई है जबकि अपीलार्थीगण को दिनांक 10.7.18 को राजस्व अपील प्राधिकारी के यहाँ से जारी केवियट के नोटिस जारी होने पर निर्णय की जानकारी हुई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावनाओं का सम्मान नहीं किया गया है तथा मनमाने तरीके से निर्णय पारित किया है। लोक अदालत में उभयपक्ष की समझाईश के आधार पर ही सहमति से निर्णय पारित किये जा सकते हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पों के अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित आराजीयात को सिवायचक दर्ज भू प्रबंध विभाग द्वारा किया गया है जिसकी दुरुस्ती हेतु वाद पत्र भू प्रबंध विभाग में वादी को करना चाहिए था जो उनके द्वारा भू प्रबंध विभाग ने नहीं कर अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से भी निरस्त योग्य होने से विधि के अनुसार ही निरस्त किया गया है। नक्शे में तरगीम भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई है जिसको वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। साबिक ख० न० 181 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा का इन्द्राज खातेदारी वादी ने गलत तरीके से राजस्व कर्मचारियों से


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

साजकर अपने हक में करवा लिया, जबकि वादी कोई भूमिहीन व्यक्ति नहीं है वादी के खाते में पहले से ही 25 बीघा से अधिक भूमि है। वादी की इस भूमि के नवीन ख०न० 321 रकबा 6 ऐयर, 322 रकबा 1.25 है०, कायम हुए हैं जिसमें से ख०न० 322 में 1 बीघा 6 विस्वा भूमि साबिक ख०न० 181 की है। वादी की भूमि साबिक ख०न० 181 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा के हाल ख०न० 321 रकबा 6 ऐयर, 322 रकबा 1.25 है० कायम हुए हैं। जिस पर वादी का कब्जा है। इस प्रकार साबिक ख०न० 181 में से वादी को 1 बीघा 1 विस्वा के स्थान पर 1 बीघा 11 विस्वा भूमि मिल चुकी है। साबिक ख०न० 181 काफी बड़ा है जिसके काफी नम्बर कायम हुए हैं मिलान क्षेत्रफल में हाल ख०न० 453 को साबिक ख०न० 181 से बनना बता दिया है जबकि यह नम्बर साबिक ख०न० 186 से बना है। हाल ख०न० 453 का इन्द्राज खातेदारी वादी के नाम गलत हो गया है। ख०न० 453 व 839/453 के किसी भी हिस्से पर वादी का कब्जा नहीं रहा है। इस भूमि पर कभी काश्त नहीं हुई है न ही काश्त के योग्य है। ख०न० 453 में चाह सार्वजनिक है। ख०न० 453 के पास में ख०न० 454 आबादी की भूमि है, ख०न० 454 के वाशिन्दों ने ख०न० 453 में सार्वजनिक चाह बनवाया है। पंचायती हथार्ई, एक शिवालय व सीताराम जी का मंदिर बनाया है। जो पुराने है। हथार्ई पर पंचायत होती है। मंदिर में लोक दर्शनार्थ आते हैं। इस भूमि में सार्वजनिक मैदान भी है। ख०न० 453 में होकर आबादी का रास्ता है। इस प्रकार ख०न० 453 व 839/453 सार्वजनिक भूमि है। न कि वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की। वादी की खातेदारी में ख०न० 181 में केवल 1 बीघा 1 विस्वा भूमि थी जिसकी एवज में उसे नवीन ख०न० 321 व 322 मिल चुके हैं। इस तथ्यों को छिपाकर वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था। ख०न० 453 से अपीलान्त/वादी का कोई संबंध वास्ता नहीं है। यह भूमि सार्वजनिक है। इस भूमि को अपीलान्त/वादी ने कभी काश्त नहीं किया है। उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कराने हेतु आम जनता ग्राम मोरपा की ओर से तहसीलदार बामनवास को प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर तहसीलदार ने मौके पर जाकर वादी हरनाथ सिंह का पुत्र रामेश्वर सिंह को तलब किया जाकर रामेश्वर सिंह के आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये हैं। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि में सार्वजनिक कुआ, मंदिर आदि का होने का स्पष्ट अंकन है। जिसके आधार पर ही तहसीलदार बामनवास द्वारा दिनांक 21.8.89 को निर्णय जारी कर ख०न० 453 में से रकबा 7 ऐयर सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये हैं। जिसकी पालना में दिनांक 23.11.89 को नामा० तस्दीक किया जाकर अमल दरामद किया गया है। इस प्रकार 7 ऐयर सिवायचक का इन्द्राज न्यायालय के आदेश के द्वारा किया गया है। जिसकी वादी/अपीलान्त द्वारा कोई अपील पेश नहीं की गई है। एक ही भूमि के बाबत वादी द्वारा दूसरा वाद पत्र अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया गया था जो भी रेसज्यूडिकेटा की श्रेणी में आता है। इस प्रकार भूमि सिवायचक दर्ज होने के कारण लोक अदालत की भावना से ही निर्णय पारित किया गया है। हाल व साबिक नक्शा ट्रेस तथा मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि हाल ख०न० 453 गत ख०न० 184 व 186 से बना है। सेटलमेंट ने हाल ख०न० 453 को साबिक ख०न० 181 से बनना बताया है जो गलत है। वादी को अपने साबिक रकबा 1 बीघा 1 विस्वा की भूमि हाल ख०न० 322 में मिल चुकी है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने माना है। इस प्रकार वादी/अपीलान्त का कोई रकबा कम नहीं हुआ है। विवादित


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आराजीयात सार्वजनिक होने से एवं आम जन का हित होने के कारण ही प्रकरण लोक अदालत मे नियत कर विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है। जो न्यायिक निर्णय है। इस प्रकार

अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादी द्वारा साबिक ख0न0 181 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा के हाल ख0न0 453 रकबा 7 ऐयर एवं ख0न0 839/453 रकबा 10 ऐयर ग्राम मोरपा का वादी को खातेदार घोषित कराने हेतु वाद पत्र पेश किया गया था। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5 समुन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 839/453 रकबा 10 ऐयर को सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने पर यह अपील पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण मे दिनांक 30.3.17 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.7.17 नियत की गई है परन्तु नियत दिनांक 6.7.17 से पूर्व ही पत्रावली 28.6.17 को पेशी पर ली जाकर आगामी पेशी दिनांक 4.7.17 नियत की गई। तत्पश्चात दिनांक 4.7.17 को पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प ग्राम पंचायत बाटोदा पर पेश हुई। जिसकी आदेशिका दिनांक 4.7.17 पर स्पष्ट उल्लेख है कि वादी उपस्थित नहीं। प्रतिवादी न0 5 उपस्थित। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की अनुपस्थिति मे प्रकरण मे निर्णय पारित किया गया है। जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से अपीलांट की अपील रिमाण्ड किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बामनवास के मु0न0 31/10 निर्णय व डिक्री दिनांक 4.7.17 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। चूकि: विवादित आराजीयात मे आम जन का हित निहित होना प्रतीत होता है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 31/10 के अंतिम निर्णय तक विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.02.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 8.1.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सावाइ भावापुर